Need to increase employability and productivity in unorganized sector -Laid

श्री राजीव राय **(**घोसी**) :** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए हाल ही में जारी किए गए अनिगमित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 की तुलना में 2022-23 में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की संख्या में 1.5% की गिरावट आई है । इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिगमित क्षेत्र में कार्य बल की कुल संख्या में लगभग 16.45 लाख की कमी आयी है यानी कार्य बल की संख्या वर्ष 2015-16 में 11.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में 10.96 करोड़ रह गई है । अकेले उत्तर प्रदेश में इन 8 वर्षों में कामगारों की संख्या में 8 करोड़ से अधिक की कमी आयी है । पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में भी स्थिति बेहतर नहीं है । गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 44 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और गैर-कृषि उद्यमों में कार्यरत लगभग 75 प्रतिशत कार्य बल को रोजगार प्रदान करता है । इन गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों के डेटा को महत्वपूर्ण रोजगार संकेत के रूप में देखा जाता है । इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां रोजगार सृजन क्षमता और श्रम बल के नियोजन को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मापदंड हैं ।

अनिगमित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट एक बहुत ही गंभीर आर्थिक परिदृश्य को उजागर करती है और यह सभी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए । यह रिपोर्ट 7-8 साल बाद सामने आई है । हम विपक्षी दल बार-बार कहते रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही है और देश खतरनाक स्तर की बेरोजगारी का सामना कर रहा है । यह रिपोर्ट उसी बात की पुष्टि करती है जो हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं । यक्ष प्रश्न यह है कि यह कार्य बल कहां गया? जब पिछले कुछ वर्षों में काम काजी आयु वर्ग की आबादी में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तब असंगठित क्षेत्र में इस क्षेत्र द्वारा पैदा होने वाले रोजगारों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है । इस दुखद स्थिति के कारणों का अनुमान लगाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है । वर्षों से दोषपूर्ण और अपरिपक्व आर्थिक नीतियां इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं । वर्ष 2016 में अनुचित ढंग से की गई नोटबंदी और वर्ष 2017 में जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी ने असंगठित क्षेत्रों की कमर तोड़ दी । कोविड-19 महामारी से स्थिति और भी बदतर हो गई । कोई सुधारात्मक कदम उठाने और इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के बजाय सरकार का ध्यान अमीरों को सहायता और लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है ।

अब समय आ गया है कि सरकार इस पर ध्यान दे और हमारी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में रोजगार क्षमता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए तंत्र तैयार करे । मैं सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह करता हूं ।